अगर सच्चाई और अच्छाई हमारे अंदर नहीं तो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलेगी।
– अज्ञात

अमेरिका और भारत के रिश्ते

सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश को अमेरिकी निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प बताते हुए कहा कि यहां न सिर्फ ज्यादा खुलापन है बल्कि दुनिया के लिए भारत भरोसेमंद भी है।

ज्योति सिंह।

भारत–चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद से अमेरिका और भारत के रिश्तों में जैसी घनिष्ठता दिखाई दे रही है, उसकी एक झलक बुधवार को आयोजित इंडिया आइडियाज समिट में भी मिली। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश को अमेरिकी निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प बताते हुए कहा कि यहां न सिर्फ ज्यादा खुलापन है बल्कि दुनिया के लिए भारत भरोसेमंद भी है।

प्रधानमंत्री ने नाम भले न लिया हो, पर इन दोनों विशेषताओं का चीन में अभाव बताया जाता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने तो इतना भी संयम बरतना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाकायदा नाम लेते हुए कहा कि भारत को चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। यह भी कि 'भारत–चीन सीमा पर टकराव की हालिया घटना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्वीकार्य व्यवहार का ताजा नमूना भर है और मुझे पूरा भरोसा है कि अपने सम्मिलित प्रयासों के दम पर हम चीन से अपने हितों की रक्षा कर लेंगे।'

बहरहाल, भारतीय सीमा पर हुई हिंसक घटना को छोड़ भी दें तो पिछले कुछ समय से चीन के व्यवहार को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी है। ऐसा सिर्फ सामरिक मामलों में ही नहीं, व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी हुआ है। हालांकि 1995 में भूमंडलीकरण की जड़ रोपते वक्त अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने चीन के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाने में ही अपना फायदा देखा था। उसके बाद के 15 वर्षों में चीन ने खुद को दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया। फिर 2008–09 की वैश्विक मंदी के बाद इन देशों को अचानक इलहाम हुआ कि चीन ने अपने सस्ते सामानों के बल पर उनके बाजार में पैठ बनाकर उन्हें सिर्फ सहूलियत ही नहीं दी है, साथ में उनके लिए बेरोजगारी का सिरदर्द भी पैदा किया है।

मंदी से मिलकर निपटने का जज्बा कुछ समय तक इस समझदारी को पीछे छोड़ने में सफल रहा, लेकिन एक सीमा के बाद इसे दबाए रखना संभव नहीं रह गया। यही कारण है कि अमेरिकी राजनीति के दोनों पक्ष आज समान रूप से चीन विरोधी हैं। पूर्वी लद्दाख या साउथ चाइना सी में चीन का रुख किसी वजह से नरम हो जाए तो भी भारत या बाकी दुनिया का व्यापारिक समीकरण उसके साथ पहले जैसा नहीं रह पाएगा।

इस बदलाव का फायदा भारत उठाए, यह वक्त की मांग है। सवाल यह है कि चीन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए भारत को अमेरिका पर कितना भरोसा करना चाहिए। याद रहे, अभी पिछले साल अमेरिका ने भारत के व्यापारिक हितों के खिलाफ कुछ कदम इतने उग्र ढंग से उठाए थे कि देश में इसके खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।

इस संदर्भ में हाल की समिट में विदेशमंत्री जयशंकर का यह बयान महत्वपूर्ण है, और इससे भारत के संतुलित रुख का संकेत भी मिलता है कि बहुध्रुवीय विश्व के साथ काम करने के लिए अमेरिका को अभी काफी कुछ सीखना है।

भौतिक संसार

अशोक वोहरा। युगों–युगों से इस संसार में आने वाले संत–महापुरुष, और दार्शनिक हमें यही बताते चले आए हैं कि सच्ची खुशी हमें अवश्य मिल सकती है लेकिन उसे हम केवल अपने अंतर में पा सकते हैं। अगर हम बाहरी दुनिया में उसे ढूंढेगे, तो हमें लगातार निराशा ही हाथ लगेगी। यदि हम इस भौतिक संसार में संपूर्णता की तलाश करेंगे, तो वो हमें कभी भी नहीं मिलेगी। खुशियों का केवल एक ही स्रोत स्थाई है, जो हवा, आग, पानी, या मिट्टी से नष्ट नहीं हो सकता। वो हमसे ना तो इस जीवन में छीना जा सकता है और ना ही शारीरिक मृत्यु के बाद। सच्ची व स्थाई खुशी केवल परमात्मा ही है। यदि हम अपने अंतर में सच्चे आत्मिक स्वरूप का अनुभव कर लेंगे, तो हमें इतनी अधिक खुशियाँ और प्रेम मिलेगा, जो इस संसार की किसी भी इच्छा की पूर्ति से हमें नहीं मिल सकता।

संपादकीय

खुद से तरक्की

एक पार्टी के रूप में नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी की कुछ बड़ी समस्याएं हैं, जिनमें धड़ेबाजी सबसे ऊपर है। पार्टी लाइन इससे आगे की चीज है, जिस पर आम राय न बन पाने के कारण इस एकीकृत कम्यूनिस्ट पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भी अभी तक आयोजित नहीं हो सका है। कोई भी कम्यूनिस्ट पार्टी वैदेशिक संबंधों को अपनी पार्टी लाइन डिबेट की धुरी नहीं बनाती, लेकिन नेपाल का मौजूदा हाल देखकर लगता है कि एनसीपी के अधिवेशन में ज्यादातर बहसें भारत और चीन के साथ नेपाल के रिश्तों को लेकर ही होंगी। आदर्श स्थिति यही होगी कि न सिर्फ यह पार्टी बल्कि नेपाल के सारे दल अपने देश को खुद से तरक्की करने वाली इकाई के रूप में आगे बढ़ाने का लक्ष्य अपने सामने रखें। भारत में किसी नेता के रवैये को लेकर मास सेंटिमेंट और पार्टी सेंटिमेंट के बीच टकराव की नौबत आती है तो जीत हमेशा मास सेंटिमेंट की होती है। लेकिन नेपाल में मामला थोड़ा अलग है। तीन दशक लंबे सघन वामपंथी आंदोलन के चलते वहां मास सेंटिमेंट ही सब कुछ नहीं रह गया है।

पूरी दुनिया में हमने कम्यूनिस्ट पार्टियों को लगातार टूटते हुए ही देखा है। नेपाल में हम कम्यूनिस्ट धड़ों को बार–बार जुड़ते देख रहे हैं और 2018 में नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी के रूप में हमने उन्हें एक बड़ी एकता की ओर बढ़ते देखा है। यह सही है कि भारी पूंजी निवेश के चलते नेपाल की जनभावना अभी चीन की तरफ झुकी हुई है और भारत विरोध की हालिया वजहें भी हम गिना चुके हैं। शायद कागजों में वे ऐसा करते भी हों। लेकिन व्यवहार में उनकी सोच पश्चिमी अनुदान और भारत–चीन खींचतान का फायदा उठाने से आगे नहीं जाती।

या फिर नेपाल के समूचे राजनीतिक माहौल में ही कोई स्थायी बदलाव आ चुका है, जिसे हम कूटनीति की अपनी पारंपरिक समझ के चलते देख नहीं पा रहे हैं?

खुराफाती रवैया

चंद्रभूषण

भारत से नेपाल के रिश्ते अभी अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे। 'रोटी–बेटी का संबंध' वाले प्रिय भारतीय राजनयिक मुहावरे के बावजूद नेपाल की राजनीति में चीन की कुछ न कुछ भूमिका बहुत पहले से रहती आई है। लेकिन यह पहला मौका है जब नेपाल सरकार को एक सीमित अवधि में एकाधिक बार चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ स्टैंड लेते देखा जा रहा है। क्या यह महज तात्कालिक मामला है? कोई राजनेता अपना नफा–नुकसान ताड़कर खामखा ऐसी बातों को हवा दे रहा है? या फिर नेपाल के समूचे राजनीतिक माहौल में ही कोई स्थायी बदलाव आ चुका है, जिसे हम कूटनीति की अपनी पारंपरिक समझ के चलते देख नहीं पा रहे हैं?

ऊपरी तौर पर एक नेता का खुराफाती रवैया ही इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार लगता है। नेपाली प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली जब 2016 में कुछ महीनों के लिए यह पद संभाल रहे थे तब उन्होंने चीन के साथ ट्रांजिट ट्रेड ट्रीटी की थी, अभी अपने देश का विवादित नक्शा पास करा लिया है, जिसमें भारत–चीन सीमा के करीब, रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कुछ जगहों को नेपाल में दिखाया गया है। वैसे तो

इस नक्शे पर नेपाल में आम सहमति बनी हुई है, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों और राजनेताओं को तो छोड़िए, ओली की अपनी पार्टी, नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी में भी शीर्ष स्तर पर यह राय जाहिर हो रही है कि भारत के प्रति नेपाली प्रधानमंत्री का रूखापन 'राजनीतिक रूप से गलत और कूटनीतिक दृष्टि से अनुचित' है।

यह राय एनसीपी के को–चेयरमैन पुष्प कुमार दाहाल 'प्रचंड' की है, जो पिछले कुछ सालों में राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ने के बावजूद नेपाल के सबसे कद्दावर कम्यूनिस्ट नेता हैं। गृहयुद्ध जीतकर संसदीय राजनीति में सफल होने वाले लोग दुनिया में कुछ गिने–चुने ही हैं, जिनमें एक नाम प्रचंड का है। उनकी समस्या यह है कि उस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले उनके दल नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दो धड़े मोहन बैद्य 'किरण' और पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के पीछे चलते हुए उनसे दूर जा चुके हैं। नेपाल में गणतंत्र की स्थापना के साथ ही प्रचंड के साथ जुड़ती गई गैर–रैडिकल छवि उनके खिलाफ गई है सो अलग। ब्यौरे में जाने के पहले हम उनकी बात को समझने की कोशिश करें। नेपाल का नया नक्शा वहां के लिए एक राष्ट्रवादी मुद्दा है, लिहाजा इस मुद्दे पर केपी शर्मा ओली का विरोध करके प्रचंड अपनी राजनीतिक कब्र नहीं खोदना चाहेंगे।

नेपाली राजनीति में उतना भारत विरोध हमेशा चलता रहा है, जितना छोटे भाई का बड़े भाई के खिलाफ यूं ही होता है। लेकिन अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नंगनाच और इसके बमुश्किल छह महीने बाद भारतीय मूल के नेपाली नागरिकों (मधेसियों) के संवैधानिक अधिकारों को लेकर भारत–नेपाल सीमा पर आयोजित 135 दिन लंबे चक्काजाम ने नेपाल में भारत की स्थिति को बहुत कमजोर बना दिया। और तो और, भारत की घोषित नजदीकी वाली नेपाली कांग्रेस भी पिछले चार वर्षों में खुलकर कोई भारत–पक्षीय बयान जारी करने में हिचकती है। तो प्रचंड अगर ओली के भारत विरोधी रुख को 'राजनीतिक रूप से गलत और कूटनीतिक दृष्टि से अनुचित' बताते हैं तो इसके पीछे उनका उद्देश्य 'भारत समर्थक' दिखना नहीं है।

अष्टयोग- 5129

	3	2	4		6	5
3	30		24	2	30	
		3	4			2
5	35		37		29	
	1	5		6		7
	31		40	4	33	
1		4				3

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5128 का हल

4	7	3	6	5	2	1
1	34	6	38	2	25	3
5	1	7	3	6	2	4
6	30	1	33	3	34	5
3	5	2	4	7	1	6
7	31	4	31	4	34	2
2	3	5	4	1	6	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

भारतीय वायरस नेपाल के लिए ज्यादा खतरनाक

मोहन। वे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 'भारतीय वायरस नेपाल के लिए ज्यादा खतरनाक है' और 'राम को अपना बताकर भारत ने नेपाल का सांस्कृतिक उत्पीड़न किया है' जैसे ओली के बयान विपक्ष को मजबूत होने का मौका दे रहे हैं और नेपाल की सौदेबाजी क्षमता घटा रहे हैं। वैसे, अभी के भेड़चाल नुमा लोकतंत्र में जनता राजनीतिक बयानों का ज्यादा महीन अर्थ नहीं ग्रहण करती, लिहाजा पूरी संभावना है कि प्रचंड को नेपाल में भारत का एजेंट मान लिया जाए, जिसके लिए केपी ओली अपनी तरफ से भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं। 'दक्षिणी पड़ोसी' की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश रची जा रही है, ऐसे बयान वे कई बार दे चुके हैं, जिसको लेकर उनके पुराने साथी भी उनसे नाराज हैं। ओली की विलय–पूर्व पार्टी एनसीपी (यूएमएल) के शीर्ष नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल और बामदेव गौतम आज भी एनसीपी की प्रमुख भूमिकाओं में हैं और मौजूदा विवाद में वे प्रचंड के साथ हैं।